(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अन्तर्गत, आवश्यक विवरण सहित प्रत्येक जिले में पता लगाए गए केन्द्रों की सूची उस जिले के लीड बैंक को दी जाती है । लीड बैंक, सभी बैंकों से प्राप्त सूचियों का समेकन करने के बाद उसे सिफारिश हेतु तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने के वास्ते जिला कलक्टर को प्रस्तुत करता है। शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990–95) के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

High level committee on tax restructure

434. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether a high level expert committee has been constituted to recommend measures to make the existing tax system more elastic broad-based and simple;

(b) if so, whether the Expert Committee has since submitted its report to Government; and

(c) if so, what are the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The report has not become due yet,

Integration of tax laws under single code

435. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state-

(a) whether Government propose to integrate laws relating to income tax, wealth tax, and gift tax under a sin gle national code for direct taxes;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what is the extent to which the proposed scheme will be more effective and useful?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR)'. (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The three Direct Tax Laws, namely, Income-tax Act, Wealth-tax Act and Gift-tax Act, were conceived as parts of an integrated system of taxation. These are now proposed to be physically integrated by means of a Direct Taxes' Code. The Code will result in,—

(i) common procedural provisions,

(ii) rearrangement of the provisions of law on a more rational basis, and

(iii) deletion of provisions which are redundant under the present law.

Consequently, the Code is expected to make the administration of tax laws easy and convenient.

Schemes to MOP up black money

436. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to launch schemes for mopping up black money;

(b) if so, what are the details thereof?

(c) the estimated black money to be recovered thereby; and

(d) by when the schemes would be launched?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The Central Government has already launched schemes for mopping up black money which are in operation at present.

Checking tax evasion and unearthing black money is a continuous exercise and steps, as deemed necessary, are taken from time to time for this purpose.

(b) to (d) In view of replyto (a) above, do not arise.

सरकार के गैर-योजना व्यय में कटौती करने के लिए कदम

437. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "हैजी पिक्चर ऑन इनफ्लेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किये गये आंकड़ों से यह पता चलता है कि खाद्यानों क उत्पादन में वृद्धि के बावजूद पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष उनके मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने सरकार के योजना भिन्न खर्च को कम करने के लिए, वर्तमान कर प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए तथा औद्योगिक संस्थाओ की उत्पादन क्षमता का इष्टतम प्रयोग को सुनिश्चित करने क लिए कदम उठाये हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस उपलब्धियां की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां । "हैजी पिक्चर ऑन इनक्लेशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार इंडियन एक्सप्रेस में 10 नवम्बर, 1991 को प्रकाशित हुआ था न कि 10 अक्तूबर, 1991 को।

(ख) चालू वित्त वर्ष 1991-92 के पहले छह महीनों के दौरान सितम्बर, 1991 तक (नवीनतम उपलब्ध) "खाद्य" समूह के लिए कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [आधार : 1990-91-100] में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई 8.5 प्रतिशत की वृधि के मुकाबले 15.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

(ग) चालू वर्ष के बजट में ब्याज की अदायगियों को छोड़कर, आयोजना-भिन्न व्यय के लिए प्रावधान 4.9 प्रतिशत रखा गया है, जो 1990-91 (संशोधित अनुमान) में रखे गए प्रावधानों से कम है । सरकार द्वारा सरकार के योजना-भिन्न व्यय को कम करने के लिए अपनाए गए उपायो में उर्वरकों तथा लेवी चीनी के लिए राजआर्थिक सहायता में कमी करना, निर्यातों के लिए नकद क्षतिपूर्ति समर्थन का उन्मूलन करना तथा 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में 5 प्रतिशत की कमी करना (इसमें सांविधिक ब्लाक ऋण/राज्यो को अनुदानों पेंशन तथा ब्याज अदायगियां आदि शामिल नहीं हैं) शामिल हैं।

(घ) सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न मुद्रास्फीति निरोधी उपायों के